भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-45

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अवसंरचनात्मक चुनौतियां

†45 श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

श्री अमर शरदराव काले:

श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

श्री संजय दिना पाटील:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण विद्यालयों को महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सामने आई ऐसी कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिजिटल अवसंरचना, विद्युत और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई है;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आईसीटी आधारित शिक्षा तक पहुंच रहित विद्यालयों का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्यालयों में डिजिटल अंतर को कम करने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों में डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(छ) सरकार द्वारा गांवों में विद्यालय की अवसंरचना का समय पर विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ज) क्या ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई विशिष्ट निधि आबंटित की गई है या प्रोत्साहन दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) & (ज): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, तथा अधिकांश स्कूल और स्कूलों में ढांचागत गतिविधियों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग यूडाइज+, प्रबंध पोर्टल और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों से निर्धारित कमी के आधार पर स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के सृजन और संवर्द्धन के लिए मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित स्कूलों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता पर हर साल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनकी आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर वृद्धिशील आधार पर विकेंद्रीकृत तरीके से काम किया जाता है और उनकी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में दर्शाया जाता है। फिर इन योजनाओं का राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन किया जाता है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी डीओएसई&एल का प्रबंध पोर्टल के माध्यम से की जाती है। राज्यों में स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में प्रगति और चुनौतियों पर विचार करने के लिए मासिक, त्रैमासिक और मध्यावधि समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों की बुनियादी ढांचे संबंधी उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

एनईपी 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और शिक्षा में डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए, समग्र शिक्षा योजना के तहत आईसीटी लैब्स और स्मार्ट कक्षा स्थापित करने के लिए निधि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में उनके द्वारा बताई गई आवश्यकता के आधार पर जारी की जाती है।

विभाग ने पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल भी अपनाई है, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है, ताकि शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच को सक्षम बनाया जा सके, जिसका लक्ष्य देश भर में लगभग 25 करोड़ स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इस पहल के प्रमुख घटक हैं

- ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) - राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म
- कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल,
- स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) - दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- डिजिटल पुस्तकों और ई-सामग्री के प्रसार के लिए ई-पाठशाला पहल,
- ईजादुई पिटारा, भौतिक जादूई पिटारा में सहयोग करने के लिए एक डिजिटल ऐप,
- दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब्स बनाई गईं, जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विज्ञान और गणित विषयों के लिए 280 वर्चुअल लैब्स उपलब्ध कराई गई हैं

इसके अलावा, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों और शिक्षकों की मांगों को पूरा करने के लिए हर जगह की स्थिति के आधार पर कार्य करें ताकि उन्हें डिजिटल रूप से पढ़ाने के लिए आवश्यक डिजिटल पहुँच प्रदान की जा सके। समग्र शिक्षा के तहत इंटरनेट, बिजली, आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम तक पहुँच रखने वाले ग्रामीण स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अवसंरचनात्मक चुनौतियों के संबंध में श्री भास्कर मुरलीधर भगरे: श्रीमती सुप्रिया सुले: डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे: श्री निलेश ज्ञानदेव लंके: श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील: श्री अमर शरदराव काले: श्री बजरंग मनोहर सोनवणे: श्री संजय दिना पाटील: प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़: द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग के उत्तर में (ज) से (क) -संदर्भित अनुलग्नक।:

समग्र शिक्षा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का ब्यौरा

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र								
		संख्या							
	कुल स्कूल	पेय जल	लड़कों का शौचालय	लड़कियों का शौचालय	रैंप	बिजली	खेल का मैदान	चारदीवारी	लाइब्रेरी/बुक बैंक/रीडिंग कॉर्नर
2021-22	59343	58830	55332	56660	57452	44606	52839	46764	58983
2022-23	58874	58457	54661	56077	57105	54098	53477	46356	58598
2023-24	58680	58187	54103	55739	56815	53532	53588	46217	58452

स्रोत: यूडाइज + 2021-22, 2022-23 और 2023-24

अनुलग्नक-II

महाराष्ट्र में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अवसंरचनात्मक चुनौतियों के संबंध में श्री भास्कर मुरलीधर भगरे: श्रीमती सुप्रिया सुले: डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे: श्री निलेश ज्ञानदेव लंके: श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील: श्री अमर शरदराव काले: श्री बजरंग मनोहर सोनवणे: श्री संजय दिना पाटील: प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़: द्वारा पूछे गए दिनांक 03.02.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के भाग (क) से (ज) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कक्षा VI और उससे ऊपर के स्कूलों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुविधा वाले सरकारी स्कूल - 2023-24				
	ग्रामीण क्षेत्र				
		संख्या			
	कुल स्कूल	इंटरनेट	बिजली	आईसीटी लैब	स्मार्ट क्लासरूम
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	132	115	132	110	112
आंध्र प्रदेश	9868	9344	9867	1745	6732
अरुणाचल प्रदेश	1180	372	754	122	407
असम	10084	5739	9609	4012	4086
बिहार	35384	5514	29082	2299	6753
चंडीगढ़	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	16524	10096	15454	1588	4525
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	187	185	187	112	171
दिल्ली	0	0	0	0	0
गोवा	100	93	100	38	58
गुजरात	19604	18656	19590	9192	15343
हरियाणा	5014	3425	5002	2452	3356
हिमाचल प्रदेश	4644	2976	4611	2549	2365
जम्मू और कश्मीर	8927	3478	8275	2023	1950
झारखंड	13574	7200	12996	2571	2819
कर्नाटक	23631	8890	23316	2778	6190
केरल	1837	1698	1832	1188	1477
लद्दाख	482	204	377	124	225
लक्षद्वीप	22	22	22	10	15
मध्य प्रदेश	30824	10303	27521	1419	7281
महाराष्ट्र	18400	9742	16698	1176	14787
मणिपुर	815	257	566	267	95
मेघालय	2204	619	738	116	71
मिजोरम	967	232	760	130	99
नागालैंड	777	367	618	126	483
ओडिशा	20229	17095	19822	6172	8699
पुदुचेरी	99	99	99	97	83
पंजाब	5718	5609	5712	4187	5505
राजस्थान	34531	24525	33708	11387	11020
सिक्किम	369	205	361	224	315
तमिलनाडु	10866	10850	10850	4449	139
तेलंगाना	8287	2507	8160	3740	3226
त्रिपुरा	1953	806	1721	596	541
उत्तर प्रदेश	46993	12205	41742	888	7999
उत्तराखंड	4480	2811	4164	770	1849
पश्चिम बंगाल	13028	7391	12760	6718	1724
भारत	**351734**	**183630**	**327206**	**75375**	**120500**